महत्वपूर्ण एवं खास

दो शिक्षकों का तबादला होने से लोगों में आक्रोश

चम्पावत (आरएनएस)। सीमांत तामली के लोगों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर सीईओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने डीएम को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने शिक्षकों की कमी के बावजूद जीआईसी तामली से दो अध्यापकों को अन्यत्र संबद्ध करने पर आक्रोश जताया है। चेतावनी दी कि यदि सीमांत के नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।गुरुवार को पूर्व प्रधान और कांग्रेस नेता विपिन जोशी के नेतृत्व में तामली के लोगों ने डीएम एसएन पांडेय को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि जीआईसी तामली में 350 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस स्कूल में पूर्व में ही एलटी वर्ग से विज्ञान और कला, प्रवक्ता वर्ग में भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, जीव विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण पद खाली चल रहे हैं।

शारदा नहर में खर पतवार का अम्बार, पानी को तरसते किसान

वर्षो से नही हुइ शारदा नहर की सफाई, खर पतवार के चलते जगंली जानवरों का बना आशियाना

उन्नाव (आरएनएस)। ब्लाक बिछिया के अन्तर्गत शारदा नहर में खडे खर पतवार के चलते किसान अपने खेतों को सींचने के लिए एक-एक बूंद पानी को तरसने को मजबूर हैं। नहर का आधा हिस्सा भारी भरकम खर पतवार से पट जाने से पानी का बहाव नाम मात्र रह गया है। नहर के दोनो पटिटयों के किनारे खडे खर पतवार में जगंली जीव जन्तुओं की शरणस्थली बनी शारदा नहर की सफाई सिचाई विभाग व्दारा आज तक नहीं कराई गई। उन्नाव ब्लाक बिछिया के अन्तर्गत ललऊखेडा, कोरारी खुर्द, अमरसस, बेहटा, चपरी, होते हुए श्रीधापुर के आगे तक जानी वाली शारदा नहर से हजारो किसानो के खेतो की सिचाई का एक मात्र साधन है लेकिन नहर के दोनो किनारो पर बडे बडे पेड व जगंली खर पतवार खडे होने से शारदा नहर पूरी तरह से जगंल में तब्दील होती जा रही है।किसानों को अपने खेत सीचने के लिए नल कूपों व तालाब के पानी का सहारा लेना पड रहा है।सरकार किसानों के हित के लिए भले ही बडे बडे दावे कर रही हो लेकिन नहरों में फैली गन्दगी व खर पतवार साफ साफ बयां कर रहा है कि सरकार किसानों के लिए कितनी संवेदनशील है।

सामान्य निर्वाचन 2017 में कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी 15 तक प्राप्त करें यात्रा भत्ता

मेरठ (आरएनएस)। अपर जिलाधिकारी प्रशासनध्उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामचन्द्र ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के समय योजित अधिकारीध्कर्मचारी जिनके द्वारा जोनल ध्सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं मतदानध्मतगणना कर्मी तथा मास्टर ट्रेनर आदि के रूप में कार्य किया गया एवं उनके द्वारा अभी तक यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं किया गया है। उन्होंने ऐसे समस्त अधिकारीध्कर्मचारी को सूचित करते हुए कहा है कि दिनांक 15 अक्टूबर 2018 तक कोषागार मेरठ से अपना भुगतान प्राप्त करें, उसके उपरान्त अवशेष धनराशि सम्बन्धित राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा कर दी जाएगी।

विवाहिता को लेने आए ससुराल वालों को मायका पक्ष ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

मेरठ (आरएनएस)। लिसाड़ीगेट निवासी एक विवाहिता को बैंग्लौर से विदा कराने आए ससुराल वालों को युवती के परिजनों ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।

जिलाधिकरी की चैखट पर पहुंचे ग्रामीणों ने नहरों में माँगा पानी

फतेहपुर (आरएनएस)। नहर विभाग द्वारा राम गंगा नहर की सिल्ट सफाई न किए जाने से जाने से अन्नदाता किसानों की धान की फसल सूखने की कगार पर आ गयी जिसकी शिकायत को लेकर भिटौरा ब्लाक के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए समस्या के निस्तारण की मांग किया। गुरुवार को अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पप्पू पाल के नेतृत्व भिटौरा ब्लाक के सलेमाबाद व गुनौर ग्राम के किसानों कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह मिलकर नहर में कई वर्षो से सिल्ट सफाई न किये जाने से कारण खेतो में पानी न आने से धान की फसल सूखने की बात कही।

रंजिश में महिला से की मारपीट की

रुडकी (आरएनएस)। लक्सर कोतवाली की रायसी चौकी के दरगाहपुर गांव निवासी महिला अपसाना ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गत दिवस गांव के चार लोगों ने रंजिश के चलते उसके घर में घुसकर मारपीट की। आरोपियों में दो पुरुष और दो महिलाएं हैं। पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है।

महिलाओं को समाज में मिले बराबरी का हक

नैनीताल (आरएनएस)। कुमाऊं विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में गुरुवार को नारीवाद विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। हर्मिटेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सोशल एक्टिविस्ट कमला भसीन रहीं। उन्होंने पितृ सत्तात्मक समाज को नारीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा रोड़ा बताया। कहा कि नारीवादी व्यवस्था का मतलब है कि महिलाओं को समाज में 50 फीसदी हक, यानि समाज में बराबरी का अधिकार मिले, जो उसे संविधान के तहत भी दिया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. डीके नौड़ियाल ने की। इस मौके पर विवि प्राध्यापक, विद्यार्थी व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

हल्द्वानी के अधिवक्ता की सड़क हादसे में मौत

रामनगर (आरएनएस)। हल्द्वानी के कैनाल कॉलोनी निवासी एक अधिवक्ता की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। इससे उसके परिवार में कोहराम मच गया। हल्द्वानी के कैनाल कॉलोनी निवासी भरत सिंह सम्मल पुत्र मान सिंह सम्मल रामनगर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता थे। वह हल्द्वानी से रामनगर प्रतिदिन आया करते थे। गुरुवार को वह स्कूटर से रामनगर आ रहे थे। छोई के पास एक कार ने उनके स्कूटर में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक मौके से वाहन को भगा ले गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधिवक्ता के शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

थाने की पुलिस फरियादियों के साथ कैसा कर रही बर्ताव

पिता बेटी की मौत के आरोपियों पर कार्यवाही के लिये चार माह से लगा रहा चक्कर नही दर्ज हुआ एफ आई आर

वही लहू लुहान महिला थाने पर लगाती है न्याय की गुहार तो उलटे पुलिस की डांट की होती है शिकार

सुल्तानपुर (आरएनएस)। संदिग्ध परिस्थितियों में बेटी की मौत के मामले को लेकर परिजन चार माह से कार्यवाही के लिये थाने का चक्कर काट रहा है लेकिन सूबे के योगी सरकार की यह मित्र पुलिस परिजनों को फटकार कर भगा दे रहे है निराश परिजनों ने पुलिस ऑफिस पहुँच कर अपर पुलिस अधीछक से मिलकर न्याय की गुहार लगाया है, मामला गोसाईगंज थाने के मगनगंज गांव का है जहाँ के रहने वाले सगीर की 13 वर्षीय पुत्री शबाना का शव उसके ही घर में बीते 11 जुलाई को फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली परिजनों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दिया मौके पर पुलिस तो पहुंची लेकिन परिजनों की तहरीर पर चार माह बाद भी मुकदमा पंजीकृत नही किया।

क्या था मामला

मृतिका शबाना के पिता सगीर के शिकायती पत्र यह बया करता है कि शबाना को गांव का लड़का बबलू परेशान किया करता था परिजनों की शिकायत पर बबलू के घर वाले आमादा फौजदारी करने के लिये खड़े हो जाते थे शबाना के पिता का कहना है कि बीते 10 जुलाई को उनकी पत्नी की तबियत खराब हो गई थी जिसको लेकर वह एक नर्सिंग होम गये हुए थे घर में शबाना अकेली थी जब दूसरे दिन सगीर अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचे तो शबाना का शरीर घर की छत से लटकता हुआ मिला जिसकी सूचना परिजनों ने स्थानीय थाने को दिया मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को दफन करा दिया।

सगीर ने पुलिस पर लगाया आरोप

मृतिका शबाना के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस अभियुक्तो के साथ मिली हुई है जिसके चलते दूसरे दिन मुझे थाने पर बुलाया गया और बेटी की मोबाइल को सबूत के तौर पर तहरीर के साथ पुलिस को दिया लेकिन कार्यवाही करने की बजाय थाने से भगा दिया गया चार माह प्रयास करने के बाद जब पुलिस ने मामले की एफ आई आर नही दर्ज किया तो पुलिस कार्यालय आकर अपर पुलिस अधीछक से मिलकर न्याय की फारियाद किया है।

दूसरा मामला गोसाईगंज थाने का

गोसाईगंज थाने का यह कोई नया मामला नही है खाकी के रौब में इस थाने की पुलिस अक्सर ऐसा वर्ताव फरियादियो के साथ करती रहती है ऐसा ही एक और मामला गोसाईगंज थाने के करखुरा गांव का है जहाँ के रहने वाली इंद्रावती पत्नी बसन्त कुमार ने पुलिस कप्तान को शिकायत पत्र देकर न्याय की फरियाद किया है कि बीते 29 सितम्बर को सुबह गांव के ही रहने वाले राम देव ,मीरा पत्नी रामदेव व प्रदीप ,जगमता लाठी डंडो से लैस होकर घर मे घुस गए और हमला बोल दिया जिसमें इंद्रावती गम्भीर रूप से घायल हो गयी जान बचाने के लिये इंद्रावती ने 100 नम्बर पर फोन किया पुलिस आई तो आरोपियों को लेकर थाने ले गई इंद्रावती भी थाने पहुंची तो पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया जब इंद्रावती घर पहुंची तो उक्त लोग पीड़िता के घर पर धावा बोलकर इंद्रावती को लहूलुहान कर दिया गांव के लोग जब मौके पर पहुंचे तो उक्त लोग भाग गए इंद्रावती दुबारा थाने पहुंची तो द्वारिका गंज चौकी भेज दिया गया पीड़िता का आरोप है कि जब वह चौकी पहुंची तो चौकी पर मौजूद पुलिस वालों ने डॉट कर भगा दिया निराश इंद्रवती इलाज के लिये जिला चिकित्सालय आई जहाँ अपना इलाज करवाया ।

इंद्रवती का पुलिस पर आरोप

इंद्रावती ने गोसाईगंज थाने की पुलिस पर आरोप लगाते हुय पुलिस कप्तान से शिकायत किया है कि उक्त लोग मादक पदार्थ का अवैध धंधा करते हैं जो उक्त थाने की पुलिस को मोटी रकम देते है जिसके चलते थाने की पुलिस कोई कार्यवाही नही करना चाहती

उत्तराखंड महिला मंच ने दिया गैरसैंण आंदोलन को समर्थन

देहरादून (आरएनएस)। गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान के आंदोलन को गुरुवार को उत्तराखंड महिला मंच ने अपना समर्थन दिया। मंच की महिला कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को मुकाम तक ले जाने का आह्वान किया।

यहां मंच की संयोजिका कमला पंत के नेतृत्व में महिलाओं ने गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाए जाने को लेकर धरना स्थल पर प्रदर्शन भी किया। कमला पंत ने कहा कि पहाड़ के विकास को लेकर अगर सरकारें गंभीर हैं तो गैरसैंण को हर हाल में स्थाई राजधानी बनाना होगा। विकास की गति तेज करने और पलायन को रोकने का एकमात्र उपाय है कि गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया जाए। इससे पूर्व कई छात्र नेताओं ने भी अभियान को अपना समर्थन दिया। पूर्व महासचिव रह चुके विपुल गौड़ ने कहा कि छात्र शक्ति को जब भी गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान बुलाएगा वह आगे बढ़कर आंदोलन में भाग लेंगे। छात्र नेता भगवती प्रसाद ने कहा कि समय आ गया है कि गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान को प्रदेश के स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचाया जाए। इसे उत्तराखंड का जन आंदोलन बनाया जाए। वहीं मेरठ विवि के छात्र नेता अंकित थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को भी गैरसैंण राजधानी अभियान से जोड़ना होगा।

इस मौके पर महिला मंच की जिलाध्यक्ष निर्मला बिष्ट, सचिव शकुंतला गुसांई, शूरवीर सिंह नेगी, आशुतोष ममगाई, जयनारायण बहुगुणा, जयकृत कंडवाल, सुरेश नेगी, मदन भंडारी, मनोज ध्यानी, मुख्य संयोजनकर्ता लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल, पूर्व सैनिक पीसी थपलियाल, जगमोहन मेहंदीरत्ता, जगदीश कुकरेती आदि रहे।

नाराज गुरिल्लाओं ने राष्ट्रपति, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

देहरादून (आरएनएस)। एसएसबी गुरिल्ला संगठन ने गुरुवार को परेड ग्राउंड धरना स्थल पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुरिल्लाओं को उपेक्षित किए जाने का आरोप लगाया। धरना स्थल पर सुबह 11 बजे के करीब गुरिल्ला एकत्रित हुए। यहां गुरिल्ला संगठन के बैनर तले प्रदर्शन किया। इसके बाद डीएम के माध्यम देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सीमा से लगे गांवों के चयनित युवक युवतियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया था। जिनमें से बाद में हजारों युवकों को स्थाई नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन बाद में वर्ष 2002 में केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को अचानक बंद कर दिया गया। जिसके बाद से ही आज तक हजारों एसएसबी स्वयं सेवक गुरिल्ला बेरोजगार चल रहे हैं। करीब 16 वर्ष बाद भी इन्हें न तो कहीं समायोजित किया गया और न ही अन्य रोजगार मुहैया करवाया गया। इसे लेकर गुरिल्लाओं में भारी रोष है।

बंद मकान के ताले तोड़ नगदी व जेवरात चोरी

रुडकी (आरएनएस)। शाहपुर गांव के ग्रामीण ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बुधवार रात उसके घर में अज्ञात युवक ने घुस कर नगदी और सामान चोरी कर लिया।

पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र के गांव शाहपुर निवासी वसीम ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात वह अपनी रिश्तेदारी में गए थे।

किसी ने उसके मकान का ताला तोड़कर 40000 की नगदी, जेवरात और बर्तन आदि चोरी कर लिए। उप निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

थाईलैण्ड में होगा 'मां गोमती आरती' कैसेट का भव्य विमोचन

तमाम लोगों के सहयोग से गायक राजेश रत्न ने दिया है स्वर

जौनपुर (आरएनएस)। आदि गंगा मां गोमती की भक्तिमय आरती सरल अंदाज में आप सबके समक्ष शीघ्र होगा। इसकी प्रस्तुति कैसेट के माध्यम से होगी जिसका विमोचन शीघ्र ही होगा। उक्त आरती को स्वर प्रख्यात गायक राजेश तिवारी रत्न ने दिया जिसकी रचना मृत्युंजय सिंह सिप्पी की है। श्री तिवारी का जन्म गोमती तटीय गांव मे होने से मां गोमती में इनकी अपार श्रद्धा है। मां गोमती के पावन आरती का विमोचन देश ही नहीं, अपितु विदेश में भी होगा। इस बात की जानकारी गायक राजेश तिवारी देते हुये बताया कि थाईलैण्ड के बैंकाक में प्रतिष्ठित गायकों, गायिकाओं सहित तमाम गणमान्य लोगों के बीच मां गोमती आरती का भव्य तरीके से विमोचन होगा। मां गोमती के महात्म्य को दर्शाती यह आरती सबको भक्तिभाव परिपूर्ण कर देगी। इस बाबत पूछे जाने पर राजेश तिवारी रत्न ने बताया कि 'मां गोमती आरती' ही शीघ्र ही अपना परचम लहराया। उनके स्वर से मां गोमती दिव्य आरती के निर्माण में बब्बा गुरू, गौतम गुप्ता, मदन सिंह, ब्रम्हेश शुक्ल, आशीष गुप्ता, शशांक सिंह रानू, अवनीन्द्र तिवारी, अवधेश पाठक, सूरज सोनी, जैकी सहित तमाम लोगों का सराहनीय योगदान है।

यूओयू के 18 पाठ्यक्रमों को यूजीसी की मान्यता

हल्द्वानी (आरएनएस)। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 18 पाठ्यक्रमों को यूजीसी से मान्यता मिल गई है। इस प्रकार यूजीसी से अब तक यूओयू के 23 पाठ्यक्रमों की मान्यता मिल चुकी है। यूओयू के पाठ्यक्रमों को 2023 तक के लिए यह मान्यता दी गई है। विवि के पाठ्यक्रमों को यूजीसी की मान्यता मिलने से यूओयू प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। पाठ्यक्रमों को मान्यता मिलने के बाद जल्द ही विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यूजीसी की कमेटी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (डीईबी) ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में चल रहे 78 पाठ्यक्रमों में से नए सत्र के लिए सिर्फ 5 पाठ्यक्रमों को ही मान्यता दी थी। इसके चलते विवि में चल रहे अधिकांश पाठ्यक्रमों के संचालन पर रोक लग गई थी। विश्वविद्यालय को सिर्फ 5 पाठ्यक्रमों को ही मान्यता मिलने से यूओयू की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए थे। इसके बाद से ही शासन और यूओयू प्रबंधन स्तर से विवि के सभी पाठ्यक्रमों को मान्यता दिलाने के

लिए प्रयास किए गए। मामले में यूओयू की ओर से यूजीसी को प्रत्यावेदन जारी किया गया। यूओयू के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. राकेश रयाल ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन व शासन के प्रयासों के चलते यूओयू के 18 पाठ्यक्रमों को फिर से 2023 तक के लिए मान्यता दे दी गई है। यूजीसी ने यूओयू को दी गई पाठ्यक्रमों की मान्यता सूची अपनी वेबसाइट में जारी कर दी है। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस

(एकल विषय), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड होटल मेनेजमेंट, मास्ट ऑफ साइंस(साइबर सेक्योरिटी), मास्टर ऑफ साइंस (इंफोर्मेशन टेक्नालॉजी), मास्टर ऑफ आर्टस (जियो इंफोर्मेटिक्स), मास्टर ऑफ आर्टस (जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन), मास्टर ऑफ साइंस (जियो इंफोर्मेटिक्स), बैचलर ऑफ होटल मेनेजमेंट, बैचलर ऑफ स्पेशल एजूकेशन (मेंटल रिटेंडिशन), बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मेनेजमेंट, मास्टर ऑफ आर्टस (साइकोलॉजी), मास्टर ऑफ कामर्स।

पर्व को देखते हुए अतिरिक्त कोच अस्थाई रूप से लगाने का निर्णय

गोरखपुर (आरएनएस)। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व में यात्रियों की होने वाली भीड़ को देखते हुए रेल प्रषासन ने 06 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में विभिन्न श्रेणी के अतिरिक्त कोच अस्थाई रूप से लगाने का निर्णय लिया है।

- 12040/12039 नई दिल्ली-काठगोदाम-नई दिल्ली एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयरकार श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच 10 अक्टूबर से 19 नवम्बर, 2018 तक लगाया जायेगा।

- 14616/14615 अमृतसर-लालकुआँ-अमृतसर एक्सप्रेस में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच 20 अक्टूबर से 17 नवम्बर, 2018 तक लगाया जायेगा।

- 22428/22427 आनन्द विहार टर्मिनस-बलिया-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस में शयनयान श्रेणी के दो अतिरिक्त कोच आनन्द विहार टर्मिनस से 13 अक्टूबर से 17 नवम्बर, 2018 तक तथा बलिया से 14 अक्टूबर से 18 नवम्बर, 2018 तक लगाये जायेंगे।

- 19409/19410 अहमदाबाद-गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक एवं साधारण द्वितीय श्रेणी के 02 अतिरिक्त कोच अहमदाबाद से 04 से 26 अक्टूबर तक तथा गोरखपुर से 06 से 28 अक्टूबर, 2018 तक लगाये जायेंगे।

- 19061/19062 बान्द्रा टर्मिनस-रामनगर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच बान्द्रा टर्मिनस से 04 से 25 अक्टूबर तक तथा रामनगर से 05 से 26 अक्टूबर, 2018 तक लगाया जायेगा।

- 19041/19042 बान्द्रा टर्मिनस-गाजीपुर सिटी-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच बान्द्रा टर्मिनस से 05 से 28 अक्टूबर तक तथा गाजीपुर सिटी से 07 से 30 अक्टूबर, 2018 तक लगाया जायेगा।

क्यारा-धनोल्टी सड़क न बनने पर ग्रामीण करेंगे चुनाव का बहिष्कार

देहरादून (आरएनएस)। रायपुर विकासखंड की न्याय पंचायत सरौना में क्यारा-धनोल्टी मोटर मार्ग न बनने से आक्रोशित ग्रामीणों ने चकराता रोड से यमुना कालोनी स्थित लोनिवि मुख्यालय तक आंख-खोलो, कान-खोलो रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण पारम्परिक ध्वनि वादक यंत्र व टार्च हाथ में लेकर पहुंचे और सड़क बनाने की मांग जोरशोर से उठायी। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अगर जल्द सड़क नहीं बनी तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा।

लोनिवि मुख्यालय में प्रदर्शन के दारान ग्रामीणों ने कहा कि क्यारा-धनोल्टी मार्ग न बनने के कारण बडेत, अमलड़यान, भमोरी, धार, खालांच, जवाला, रगड़, उटियाणू, बटवाला, लग्गा आदि मजरें विकास में पिछड़ गए हैं। इसके अलावा गांवों के काश्तकारों को फसल को मंडी में ले जाने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सड़क न बनने से छात्रों को लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। इसके साथ ही बुजंर्गों व प्रसुति महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस मोटर के निर्माण के लिए कई साल से आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया है कि यदि इस मोटर मार्ग के निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं किया तो क्षेत्रवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य महादेव भट्ट ने कहा कि देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर की दूर होने के बावजूद उक्त क्षेत्र आज भी विकास की राह देख रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र को दुर्गम व पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग भी सरकार से की। मौके पर महेंद्र प्रताप सिंह नेगी, राजकुमार जयसवाल, कविंद्र इष्टवाल, प्रधान सुंदर सिंह पयाल, सैरा गांव प्रधान कृपाल रतन सिंह रावत, देवेंद्र दत्त, बिजेंद्र सिंह चंदेल, बचन सिंह, सोबन सिंह रावत, मंगल सिंह रावत, दीवान सिंह रावत, कलम सिंह नेगी, प्यारे लाल, सीतरा राम जोशी, गंभीर सिंह रावत, पूरण सिंह रावत, प्रतीम दास, उत्तम दत्ता, चमन दास, विनोद डोभा आदि मौजूद रहे।

डेंगू फैलने की सूचना पर पहुंची टीम

रुडकी (आरएनएस)। लिब्बरहेड़ी गांव में डेंगू फैलने की शिकायत जेएम रुड़की से की गई। जेएम ने मंगलौर सीएचसी को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची तथा 27 लोगों के सैंपल लिए। लिब्बरहेड़ी गांव निवासी कुछ लोग प्रार्थना पत्र लेकर जेएम नितिका खंडेलवाल के पास पहुंचे। उनका कहना था कि गांव में डेंगू फैला हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नागरिकों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जेएम ने सीएचसी मंगलौर को निर्देश दिए। जेएम के आदेशों के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची।

टीम ने 27 लोगों के रक्त नमूने लिए तथा उन्हें दवा वितरित की। सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. पीके सिंह ने बताया कि गांव में किसी भी मरीज में डेंगू लक्षण नहीं पाए गए। केवल साधारण बुखार के मरीज मिले हैं। रक्त नमूने ले लिए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। टीम में सुभाष कुमार, रमरति, मेमत आदि शामिल रहे।

बांस व मूनाकोट पॉलिटेक्निक के लिए धन अवमुक्त करने को सीएम को भेजा पत्र

पिथौरागढ़ (आरएनएस)। भाजपा नेता सुरेश जोशी ने चंडाक क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। गुरुवार को प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने नाकोट,कालसिन कटिया,डुंगरा,माणा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बांस में बने पालिटेक्निक कॉलेज में कक्षायें शुरु नहीं होने की समस्या उठाई। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी बांस कॉलेज संचालित नहीं होना गलत है।

भाजपा सरकार ने 2011-12 में पॉलिटेक्निक कालेज मूनाकोट व बांस के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। संचालित होने के 16 वर्ष बाद भी मूनाकोट भवन का कार्य आधा अधूरा पड़ा है। उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज बांस व मूनाकोट के लिए मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर शेष धन अवमुक्त कराने की मांग की है।